



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]  
No. 106]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019  
सं. 83 / 2015–2020

**विषय:** एमईआईएस प्रकार के तंत्र के तहत आरओएससीटीएल हेतु स्क्रिप्ट जारी करने हेतु वस्त्र मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी में छूट देने हेतु स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया पुस्तक के अंतर्गत प्रावधानों को जोड़ना।

**फा. सं. 01/61/180/360/ ए.एम.19/पीसी-3.**— विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में निम्नलिखित पैराओं को तत्काल प्रभाव से जोड़ते हैं।

**4.95 राज्य और केन्द्रीय लेवी और कर में छूट (आरओएससीटीएल)** हेतु स्कीम हेतु आवेदन की प्रक्रिया

क) विदेश व्यापार नीति का पैरा 4.01 (ग) आरओएससीटीएल के बारे में है। वस्त्र मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं. 14 / 26 / 2016—आईटी (खंड II) दिनांक 07.03.2019 में वस्त्र क्षेत्र (वस्त्रों और निर्मितियों हेतु) की सहायता हेतु राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) के लिए स्कीम के प्रावधानों को रेखांकित करती है।

ख) स्कीम के अंतर्गत छूट की दरों को वस्त्र मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं. 14 / 26 / 2016—आईटी (खंड II) दिनांक 08.03.2019 के तहत अधिसूचित किया गया है। आरओएससीटीएल स्कीम की दरों को अधिसूचना की 1, 2, 3 और 4 अनुसूचियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनुसूची 1 और 2 परिधानों और निर्मितियों हेतु क्रमशः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी की दरें हैं। अनुसूची 3 और 4 परिधानों के निर्यात पर लागू

क्रमशः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी की दरें हैं जब विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत केवल फैब्रिक (इंटरलाइनिंग सहित) का शुल्क मुक्त आयात किया गया हो।

ग) आरओएससीटीएल के तहत निर्यात पर छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन एएनएफ 4 आर में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए डीजीएफटी की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर ऑनलाईन किया जाएगा। संबंधित शिपिंग बिलों को निर्यातक ऑनलाईन आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ लिंक किया जाएगा। आरओएससीटीएल हेतु आवेदन करने के लिए ई-बीआरसी को लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाईन मोड्यूल में निर्यातक द्वारा एक एकल आवेदन में अधिकतम 50 शिपिंग बिलों को जोड़ना अनुमत होगा।

घ) स्प्लिट स्क्रिप्टों की सुविधा: प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.09 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ङ.) आरओएससीटीएल के आवेदन हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.06 (ख) के अनुसार होगा। आवेदक सुनिश्चित करेंगे कि स्क्रिप्ट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.06 (ख) के अनुसार वे क्षेत्राधिकार के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ही आवेदन कर रहे हैं तथा स्क्रिप्ट हेतु ऑनलाईन आवेदन करते समय इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे। तथापि वित्तीय वर्ष की शुरूआत में क्षेत्रीय प्राधिकारी को चुनने तथा उस वित्तीय वर्ष में सभी आवेदनों हेतु उसी क्षेत्रीय प्राधिकारी को बनाए रखने संबंधी पैरा 3.06 (क) में लगाई गई पाबंदी लागू नहीं होगी।

च.) आरओएससीटीएल स्क्रिप्ट के लिए पंजीकरण के पत्तन का चयन: ऑनलाईन आवेदन करते समय

- ईडीआई पत्तनों और गैर-ईडीआई पत्तनों से शिपमेंट को एक आवेदन में कलब नहीं किया जा सकता है।
- आवेदक जहां से निर्यात किया जाता है ऐसे पत्तनों में से किसी एक पत्तन से ईडीआई समर्थित पत्तनों हेतु पंजीकरण के पत्तन का चयन कर सकता है।
- गैर-ईडीआई पत्तन के माध्यम से निर्यात के मामले में, पंजीकरण का पत्तन निर्यात का संगत गैर-ईडीआई पत्तन होगा। तदनुसार, प्रत्येक गैर-ईडीआई पत्तन हेतु अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

छ) डीजीएफटी ऑनलाईन प्रणाली आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रक्रियाबद्ध करेगी और स्क्रिप्ट को प्रणाली आधारित अनुमोदन और जांच तंत्र के आधार पर जारी किया जाएगा। प्रणाली आधारित अनुमोदन के बाद, ईडीआई शिपिंग बिल विवरण का पुनः सत्यापन किए बिना आरए द्वारा स्क्रिप्ट जारी किया जाएगा। स्क्रिप्ट को ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर व्यक्तिगत रूप से या डाक से वितरित किया जाएग।

ज) स्क्रिप्टों का पंजीकरण: आरओएससीटीएल के तहत जारी किए गए स्क्रिप्टों के पंजीकरण का पत्तन निम्नानुसार होगा:

- शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट (स्प्लिट सहित) पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो ईडीआई पत्तनों में से कोई भी एक हो सकता है जहां से निर्यात किया जाता है। गैर ईडीआई पत्तनों से शिपमेंट के मामले में, आरओएससीटीएल के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट स्प्लिट सहित पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो निर्यात का पत्तन होगा।
- शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट पर उल्लिखित पत्तन पर पंजीकृत कराने की आवश्यकता है। यह शुल्क क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देने से पहले किया जाना है। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत हो जाने पर स्क्रिप्ट का स्वचालित रूप से आयात हेतु किसी भी ईडीआई पत्तन पर और टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) प्रक्रिया के तहत किसी भी मैनुअल पत्तन पर उपयोग किया जा सकता है।
- यदि पंजीकरण का पत्तन हस्तचालित पत्तन है, तो किसी अन्य पत्तन पर आयात हेतु टीआरए की आवश्यकता होगी।

झ) वैधता अवधि और पुनर्वधीकरण: शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट जारी होने की तिथि से 24 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा और उस तिथि पर वैध होगा जिस तिथि पर शुल्क का वास्तविक डेबिट किया जाता है। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट

का पुनर्वैधीकरण अनुमत नहीं होगा जब तक कि इसे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.20(ग) के तहत कवर न किया गया हो।

ज) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: आईसीईजीएटीई से डीजीएफटी सर्वर पर शिपिंग बिल अपलोड करने की तिथि से एक साल के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस अवधि के बाद, कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और शिपिंग बिल कालातीत हो जाएंगे। आरओएससीटीएल के तहत विलंब कटौती का कोई भी प्रावधान नहीं है। स्कीम केवल दिनांक 31.03.2020 तक किए गए निर्यात हेतु वैध है।

ट) आरए में गैर ईडीआई शिपिंग बिलों को प्रक्रियाबद्ध करना: गैर ईडीआई शिपिंग बिलों के मामले में संबंधित आरए स्क्रिप प्रदान करने से पहले मूल शिपिंग बिल से निर्यातक द्वारा भरे गए विवरण को सत्यापित करेगा।

ठ) प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.24 के प्रावधनों के अंतर्गत आरओएससीटीएल के तहत डूप्लीकेट स्क्रिप जारी किया जा सकता है।

ड) उन इकाइयों/आईईसी जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची में हैं, को छोड़कर सभी निर्यातक आरओएससीटीएल के अंतर्गत दावा करने के लिए पात्र हैं।

#### **4.96 वसूली तंत्र**

क) आवेदक को निर्यात से संबंधित शिपिंग बिलों और दस्तावेजों का अभिलेख निर्गम के पश्चात जांच और वसूली प्रयोजनों के लिए स्क्रिप जारी होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए संभाल कर रखना है। लाइसेन्सिंग प्राधिकारी तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय इन मूल दस्तावेजों की मांग कर सकता है। यदि आवेदक लाइसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा मांगे गए मूल दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आवेदक को प्रदान की गई छूट स्क्रिप जारी होने की तारीख से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 क के तहत निर्धारित दर पर ब्याज के साथ लौटाना होगा।

ख) साथ डी, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां निर्यातक के आवेदन के आधार पर आरओएससीटीएल के अंतर्गत पात्र राशि से अधिक राशि जारी की गई है, ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी संगत स्क्रिप के इलेक्ट्रानिक रिकार्ड की जांच करेगा और यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी को चअत्यधिक दावा/अत्यधिक संवितरण का पता चलता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी फर्म से विसंगति के बारे में स्पष्ट करने के लिए अनुरोध करेगा। यदि छूट की अत्यधिक राशि साबित हो जाती है तो आवेदक विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19 में यथा विहित ब्याज के साथ अत्यधिक दावा का रिफंड करेगा।

ग) यदि आवेदक उपरोक्त यथा निर्धारित अत्यधिक दावा रिफंड नहीं करता है या क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा भेजे गए इससे संबंधित पत्र का 30 दिनों के भीतर जबाब नहीं देता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी एफटी (डी एवं आर) अधिनियम और नियमावली के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा।

घ) अनुमत छूट विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनुमत समय के भीतर बिक्री से लाभ की प्राप्ति के अधीन है जिसके न होने पर ऐसी छूट को कभी—भी अनुमत नहीं होने के रूप में माना जाएगा। गलत या अधिक आरओएससीटीएल भुगतान की चुकौती के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा एफटी (डी एवं आर) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, निर्यात की गलत गणना से उत्पन्न स्क्रिपों के माध्यम से जारी छूट के किसी अत्यधिक भुगतान को लौटाना अनिवार्य है। जहां पुनर्भुगतान, वसूली या वापसी का मामला है तो निर्यातक द्वारा स्क्रिप के डेबिट होने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक परिकलित 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। यदि निर्यातक अप्रयुक्त स्क्रिप वापस कर देता है तो कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा, तथापि, गलत घोषणा या कपटपूर्ण व्यवहार के आधार पर न्यायनिर्णय के आदेश के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा राज्य और केन्द्रीय कर एवं लेवी से छूट की स्कीम के संबंध में वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 14 / 26 / 2016—आईटी (खंड II) कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक में समुचित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

**आलोक वर्धन चतुर्वेदी  
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव**

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 29th March, 2019

No. 83/2015-2020

**Subject: Addition of provisions under the Handbook of Procedures for implementation of the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies, as notified by the Ministry of Textiles for issuance of scrip for RoSCTL under a MEIS type mechanism**

**F. No. 01/61/180/360/AM19/PC-3.—** In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby adds the following paras in the Chapter 4 of the Handbook of Procedures, with immediate effect.

**4.95 Procedure to apply for the Scheme for Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL)**

a. The para 4.01 (c) of the FTP is about the RoSCTL. The Gazette Notification of the Ministry of Textiles no. 14/26/2016-IT (Vol II) dated 07.03.2019 outlines the provisions of the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) to support the Textile Sector (for garments and made-ups).

b. The rates of Rebate under the scheme have been notified vide the Gazette Notification of the Ministry of Textiles No. 14/26/2016-IT(Vol – II) dated 08.03.2019. The rates of RoSCTL Scheme are notified as Schedules 1, 2, 3 and 4 of the notification. The Schedule 1 and 2 are the rates of State and Central taxes and levies respectively, for apparel and made-ups. Schedules 3 and 4 are the rates of State and Central taxes and levies respectively, applicable for apparel exports when the fabric (including interlining) only has been imported duty free under Special Advance Authorization Scheme.

c. An application for claiming rebate under RoSCTL on exports, shall be filed online, using digital signature, on DGFT website at <http://dgft.gov.in> with RA concerned in ANF4 R. The relevant shipping bills shall be linked with the on-line application by the exporter/ applicant online. There would be no requirement of linking e BRCs for applying for RoSCTL. A maximum of 50 shipping bills would be allowed to be attached in one single application by the exporter in the online module.

d. Facility of Split Scrips: Provisions of para 3.09 of the HBP shall apply mutatis mutandis.

e. The Jurisdictional RA for application of the RoSCTL would be as per the para 3.06 (b) of the HBP. The applicants shall ensure that they are applying only to the concerned Jurisdictional RA, as per para 3.06 (b) of the Handbook of Procedures for getting the scrip and shall submit a declaration to that effect while applying for the scrip online. However, the limitation imposed in para 3.06 (a) regarding choosing a RA at the beginning of financial year and maintaining the same RA for all applications in that Financial year shall not apply.

f. Choice of Port of Registration for RoSCTL Scrips: While making an online application

i. Shipments from EDI Ports and Non-EDI Ports cannot be clubbed in one application.

ii. The applicant can chose the Port of registration for EDI enabled ports from any one of the ports from where export is made.

iii. In case of exports through non-EDI port, the port of registration shall be the relevant non-EDI port of exports. Accordingly, separate application shall be filed for each non-EDI port

g. The DGFT online system shall electronically process the online applications and scrip shall be issued based on a system based approval and check mechanism. After system based approval, scrips will be issued by RAs without cross verifying EDI Shipping Bill details. The Scrip would be delivered by hand or by post, based on the option selected by the applicant while applying online.

h. Registration of Scrips: Port of Registration of Scrips issued under RoSCTL would be as follows:

1. Duty Credit Scrip (including splits) shall be issued with a single port of registration which shall be any one of the EDI ports from where export is made. In case of shipments from Non EDI ports, the Duty Credit Scrip (including splits) under RoSCTL shall be issued with a single port of registration which shall be the port of export.

2. Duty credit scrip needs to be registered at the port mentioned on the scrip. This is to be done prior to allowing usage of duty credit. Once registered at EDI port, scrip can be automatically used at any EDI port for import and at any manual port under Telegraphic Release Advise (TRA) procedure.

3. In case port of registration is a manual port, TRA shall be required for imports at any other port.

i. Validity period and Revalidation: Duty Credit Scrip shall be valid for a period of 24 months from the date of issue and must be valid on the date on which actual debit of duty is made. Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under paragraph 2.20(c) of HBP.

j. Last date of filing of application for Duty Credit Scrips: The application will have to be filed within one year of the date of uploading of the shipping bills from ICEGATE to DGFT server. After this period, no application can be filed and the shipping bills would be time barred. There is no provision of late cut under RoSCTL. The Scheme is valid for exports made upto 31.03.2020 only.

k. Processing of Non EDI Shipping bills at RA: In case of Non EDI shipping bills concerned RA shall verify the details entered by the exporter from the original shipping bills before grant of scrip.

l. A duplicate scrip may be issued under the RoSCTL, under the provisions of the para 2.24 of the Handbook of Procedures 2015-20.

m. All exporters are eligible for making a claim under the RoSCTL, except the entities/IEC which are in the Denied Entity List of the DGFT.

#### **4.96 Recovery Mechanism**

a. The record of shipping bills and other documents related to export, is required to be maintained by the applicant for a period of 3 years from the date of issuance of scrip for post issue scrutiny and recovery purposes. Licensing Authority may call such documents in original at anytime within 3 years. In case the applicant fails to submit the original documents on demand by Licensing Authority, the applicant shall be liable to refund the rebate granted along with interest at the rate prescribed under Section 28AA of Customs Act 1962, from the date of issuance of scrip.

b. Also, there can be instances, where based on the application of the exporter, amount more than the eligible amount has been issued under RoSCTL; in such cases, concerned RA will examine the relevant scrip's electronic records and in case, an excess claim/ excess disbursal is taken note of by the RA, the RA would request the firm to explain the discrepancy. In case an excess grant of rebate is established, the applicant shall refund the excess claim with interest as prescribed in paragraph 3.19 of FTP

c. In case the applicant fails to refund the excess claim as stipulated above or does not respond to any communication by RA within 30 days of receipt of such communication, RA will initiate action as per FT(D&R) Act and Rules.

d. The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed. Action under the FT(D&R) Act may be taken by the Regional Authorities for repayment of erroneous or excess paid RoSCTL. Further, the exporter is required to return any over-payment of rebate issued through the scrips arising from miscalculation. Where there is repayment, recovery or return, interest shall also be paid by exporter at the rate of fifteen percent per annum calculated from the date of debit of the scrip till the date of repayment. In case the exporter returns the un-utilized scrips, no interest will be charged, however, penalty may be imposed under an Adjudication order on the grounds of mis-declaration or fraudulent practice.

**Effect of this Public Notice:** Suitable provisions has been inserted in the Handbook of Procedures, to implement the Ministry of Textiles Notification No. 14/26/2016-IT ( Vol II) dated 07.03.2019 regarding the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies by the DGFT.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI,  
Director General of Foreign Trade and  
Ex-Officio Add. Secy.